गैर-विकास व्यय की वार्षिक दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जो व्यय दर 1985-90 के दौरान 18.2 प्रतिशत और 1999-95 के दौरान 20.9 प्रतिशत थी वह 1998-99 के दौरान बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-विकास व्यय में वार्षिक वृद्धि के संबंध में सरकार का आकलन क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन "फाइनेंसेज ऑफ स्टेट गर्वनमेंट 1998-99" (राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था 1998-99) में राज्यों के गैर विकास खर्चों में हो रही लगातार वृद्धि संबंधी तथ्यों को दर्शाया गया है।

Hike in Customs Duty on Gold

*13. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have recently increased customs duty on gold import and if so, the details thereof and the reasons therefor:

(b) whether Government are aware that as a result of the increase in the customs duty on gold, Dubai gold trade would immensely benefit as N.R.Is. will buy more jewellery to carry home as gold in India has become more expensive; and

(c) if so, what is Government's reaction in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Yes Sir, the government have increased the rate of duty on gold import from Rs. 250 per 10 gms. to Rs. 400 per 10 gms. with effect from 5.1.99 vide notification No. 2/99-Cus. dated 4.1.99. It was considered appropriate to increase the duty in order to moderate the abnormally high quantum of imports and also to garner additional revenue to the extent possible.

(b) and (c) The rate of duty on gold and gold jewellery is identical. Government does not apprehend any harm to the finances of the country as a result of the increase of import duty on gold.

जीवन बीमा निगम के हजारीबाग डिवीजन में सहायक के पदों के लिए रिक्तियां

*14. श्री राजनाथ सिंह:

श्रीमती मालती शर्मा:

क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1738 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम, हजारीबाग डिवीजन, बिहार में 157 सहायकों की नियुक्ति के लिए तीन वर्ष पूर्व बनाए गए पैनल के लिए कब तक पद रिक्त होने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस डिवीजन में अनेक पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है लेकिन इसके बावजूद प्रबंधक द्वारा नियुक्तियों में विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक हजारीबाग डिवीजन में कितनी रिक्तियां चिन्हित की गई हैं और इन 157 सहायकों को कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) बदलती हुई व्यसायगत आवश्यकताओं के अनुसार, जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की स्थिति के पैटर्न का पुनरीक्षण कर रहा है और नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है। इसलिए ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि इस पैनल के लिए कब तक रिक्तियां निकलेंगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जीवन बीमा निगम किसी विशेष अवधि के लिए रिक्तियों को चिन्हित करने की प्रणाली का अनुपालन नहीं करता जो पैनल तैयार किया गया है उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है और जब कभी भी रिक्तियां होंगी तभी उन्हें भरा जाएगा।

कर विवाद समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

*15. श्री राघवजी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1999 को समाप्त हुई कर विवाद समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;